भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2032
दिनांक 11 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

ओडिशा में डेयरी को बढ़ावा देना

2032. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओडिशा में, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के विकास और डेयरी किसानों को वित्तीय सहायता के संदर्भ में डेयरी को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत ओडिशा में स्थापित डेयरी फार्मों और सहकारी समितियों का ब्यौरा क्या है और स्थानीय आजीविका पर उनका क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या मंत्रालय ने राज्य में, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डेयरी उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ाने के लिए कोई पहल की है; और

(घ) ओडिशा में डेयरी किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे पशु चिकित्सा देखभाल, चारा आपूर्ति और उचित मूल्य निर्धारण तक पहुंच के समाधान के लिए क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग दूध प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को पूरित और संपूरित करने के लिए ओडिशा सहित पूरे देश में निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

(i) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी); एनपीडीडी योजना के अंतर्गत, ओडिशा में 62.60 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा 55.33 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ 7 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं, इसमें से अब तक 46.78 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

(ii) डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ): ओडिशा में, ओडिशा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक परिसंघ (ओएमएफईडी) को 58.45 लाख रुपये (नियमित और अतिरिक्त सबवेंशन सहित) का ब्याज सबवेंशन संस्वीकृत किया गया है।

(iii) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ): एएचआईडीएफ के तहत, ओडिशा में 32.70 करोड़ रुपये (15.04 करोड़ रुपये का ऋण) के परिव्यय के साथ तीन परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं।

अब तक, एनपीडीडी, राष्ट्रीय डेयरी योजना और सरकारी योजनाओं के तहत 6523 सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं जिनके 3.36 लाख किसान सदस्य हैं। ये योजनाएं डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने और डेयरी फार्मिंग से आय बढ़ाने के लिए संगठित बाजार उपलब्ध कराने संबंधी मदद कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त ओडिशा सरकार पांच वर्षों के लिए 1,423.47 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री कामधेनु योजना कार्यान्वित कर रही है। इसका उद्देश्य योजना के तहत छोटी डेयरी इकाइयों की स्थापना, बछड़े-बछड़ियों के सब्सिडी वाले चारे, पशुधन बीमा के तहत कवरेज बढ़ाने और डेयरी सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2024-25 के लिए डेयरी कार्यकलापों हेतु 65.49 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

(ग) से (घ) पशुपालन और डेयरी विभाग निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है, जिससे बोवाइन पशुओं की दूध उत्पादकता में सुधार लाने, आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ाने तथा पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद मिल रही है।

(i) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)

(ii) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)

(iii) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी)

इन उपायों से दूध उत्पादन की लागत कम करने में मदद मिलती है और डेयरी फार्मिंग से आय बढ़ाने में भी मदद मिलती है।

इसके अलावा एनडीडीबी ने ओडिशा में डेयरी क्षेत्र के संधारणीय विकास के लिए उनके डेयरी सहकारी संस्थानों को पुनर्जीवित करने में सहायता हेतु सितंबर 2024 में ओडिशा राज्य सहकारी दूध उत्पादक परिसंघों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

******